(c) Operation of the only available plane is under the control of Indian Railway Construction Company (IRCON) Ltd.

रेलवे फाटकों पर उपरि पुलों का निर्माण

3992. श्री रामजीलाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे ने कितने रेलफाटकों पर उपरि पुल (ओवरब्रिज) बनाए हैं और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दुर्घटनाप्रवरण रेल फाटकों पर उपरि पुल बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिसार में डबल रेल–फाटक (ठण्डी सड़क) पर सरकार उपरि पुल बना रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे पुलों का निर्माण करने की ओर ध्यान देगी; यदि हां, तो ठण्डी सड़क हिसार में उपरि पुल के कब तक बन जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ): 55 ऊपरी/निचले पुलों पर रेलवे के भाग का काम पूरा हो गया है।

राज्य	ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
1	2
असम	1
आन्ध्र प्रदेश	14
बिहार	1
दिल्ली	1
हरियाणा	1
कर्नाटक	5
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	11
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	5
कुल	55

(ख) रेलें केवल उन्हीं व्यस्त समपारों पर जहां से होकर एक लाख या उससे अधिक गाड़ी वाहन यूनिट (यह वह संख्या है जिसे 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या के सड़क यातायात द्वारा गुणा करके प्राप्त किया जाता है) गुजरती है, के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण पर विचार करती हैं बशर्ते कि राज्य सरकार नियमानुसार अपने हिस्से की लागत वहन करने की विधिवत् सहमति सहित एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी व्यस्त समपार के बदले में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की प्रणाली यह है कि राज्य सरकारें प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्माण कार्यों का प्रस्ताव करती हैं। तत्पश्चात् रेलवे मामलों की जांच करती हैं और उनमें से ऐसे कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करती हैं, जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पूर्वपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी है।

ठंडी सड़क हिसार में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Cash and carry scheme

3993. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cash and carry scheme of the railways to move coal to thermal power station has come a cropper;

(b) if so, the reasons for the coal cash and carry scheme resulting in a flop;

(c) what is the amount outstanding against the National Thermal Power Corporation and various State Electricity Boards and how the Railways propose to recover the same, when Railways' own finances are in a critical shape; and

(d) whether Government would consider/approaching the Ministry concerned with the grant of central assistance to the States to recover their dues from the allocated central plan aids?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) No, Sir. Instructions for compulsory prepayment of freight for coal moved to certain Power Houses were issued as the dues to the Railways from these Power Houses were substantial. On receipt of representations from some of these undertakings that these instructions would result in disruption of power generation, they were withdrawn in their case.

(c) and (d) The amount outstanding against National Thermal Power Corporation is Rs. 539.30 crores and the dues outstanding